



शुक्रवार सुबह विधानसभा परिसर में हुई वोटिंग में 86 विधायकों ने वोट डाला

ट्रंप ने ऑटारियो सरकार के रॉनल्ड रीगन सम्बंधी विज्ञापन को "धोखा" बताते हुए वार्ता समाप्त करने की घोषणा की

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैसे भी, रूसी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और देश के आयात के लिए तेल के अलावा, ज्यादा कुछ नहीं है। तेल निर्यात से होने वाली आय सरकार के पास जाती है और इसी से युद्ध को वित्तीय सहायता मिलता है। ट्रंप और उनके सलाहकार समूह लंबे समय से इन आर्थिक रास्तों को बंद करने की योजना बना रहे थे, ताकि पुतिन के लिए यह युद्ध की फगिंग मुश्किल हो जाए।

डॉनल्ड ट्रंप अब तक रूस और पुतिन के युद्ध के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से बचते रहे थे, इस उम्मीद में कि कथमकियाँ काम करेंगी और पुतिन बातचीत की मेज पर आएँगे। हालाँकि, जब भी पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला।

ट्रंप ने स्वयं पुतिन के साथ अपनी निजी कूटनीति की विफलता स्वीकार करते हुए कहा कि उनको बातचीत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया है।

दूसरी ओर, इन प्रतिबंधों का असर भारतीय रिफाइनरियों पर पड़ने लगा है और ऐसी खबरें हैं कि कुछ बड़ी निजी तेल रिफाइनरियाँ अथवा रूसी कच्चे तेल से दूरी बना रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, गुजरात स्थित अपनी रिफाइनरी के लिए सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदती थी। कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए उसका रोसेनफेल्ट के साथ बीस साल का अनुबंध है। भारत प्रतिदिन लगभग 17 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात करता था। इसमें से एक बड़ा हिस्सा विशाल रिलायंस रिफाइनरी के लिए था। अन्य निजी रिफाइनरियाँ और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियाँ भी रूसी कच्चा तेल खरीदती थीं।

रिलायंस के लिए रूसी कच्चे तेल से दूरी बनाना बहुत असमंजस है, क्योंकि किसी भी तरह के वित्तीय प्रतिबंध का अंतर्राष्ट्रीय बैंक और बाजारों तक उसकी पहुँच पर रोक लगने से गंभीर परिचालन समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। वैश्विक

पूँजी बाजारों तक उसकी पूरी पहुँच बाधित हो सकती है। रिलायंस मध्य पूर्व के उत्पादकों और लैटिन अमेरिकी तेल कंपनियों से कच्चे तेल की आपूर्ति की तलाश कर रही है। कुछ अन्य भारतीय कंपनियाँ, जैसे नायरा एनर्जी, के पास बहुत कम विकल्प हैं, क्योंकि उस पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है।

उद्योग जागत के जानकार लोगों का मानना है कि शुरुआत में रूस से तेल की आवश्यकता में गंभीर गिरावट आ सकती है, लेकिन, मध्यम से लंबी अवधि में रूसी तेल की बिक्री के वैकल्पिक रास्ते सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, आयात की औसत मात्रा लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन पर ही बनी रह सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के बाद, रूस के पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा, अन्य कोई विकल्प नहीं होगा।

आखिरकार, धन ही किसी भी युद्ध की रीढ़ होता है।

किलोग्राम मेथामफेटामाइन और इससे बनाने में इस्तेमाल होने वाले 110.923 किलोग्राम रसायन मिले।

तलाशी के दौरान वहाँ से कई संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई के अनुसार इस अभियान में उसके अधिकारियों को विभिन्न अधिकार क्षेत्रों (नोएडा (उत्तर प्रदेश), गुरुग्राम (हरियाणा) और दिल्ली) और चुनौतीपूर्ण जगहों पर कार्रवाई करनी पड़ी। यह जटिल अभियान खुफिया जानकारी और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से किया गया।

राहुल ने सीताराम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधायकता चुनाव के बीच के सेरी की पुण्यतिथि पर पिछले 25 साल में शावद पहला अवसर है, जब गांधी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2025-26 में छात्रों को 4,240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा

गहन पुनराक्षण

तमिलनाडु व आंध्र के तटवर्ती जिलों के लिए अलर्ट जारी

देहरादून, 24 अक्टूबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि इस साल चार धाम यात्रा में लगभग 50

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रदेश के कुरलूल में एक दुखद बस अग्निकांड में हुई मौतों की खबर बेहद दर्शायमान है। मैं शोक संतप्त परिवार परिजनों को 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। मध्यमंत्री चंद्रबाबु नाइडु ने मारे अपने राज्य के 6 लोगों के आंध्रप्रदेश पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विशेष पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएँ, जो स्कूली स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आती हैं, उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा देवनागरण छात्र छात्राएँ वितरण योजना के तहत, अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपये व्यय कर 16 हजार 21 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। साथसाथ ही, प्रोत्साहन राशि में 9 करोड़ 76 लाख रुपये व्यय कर 19 हजार 100 छात्राएँ लाभान्वित की जा चुकी हैं।